देश में खाद्य तेल की आवश्यकता

4482. **श्री दिलीप सिंह जुदेवः** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषतः गुजरात और मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 तक खाद्य तेल की कुल कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी;

(ख) इस संबंध अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) सरकार द्वारा देश में खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त राज्यों में अनुमानित खाद्य तेल का वार्षिक उत्पादन कितना- कितना है; और

(ड.) देश में उत्पादित और विदेशों से आयातित खाद्य तेल के मूल्यों में क्या अन्तर है?

कृषि मंत्री खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) इस मंत्रालय के पास खाद्य तेलों की राज्यवार आवश्यकता के बारे में कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। तथपि, नवीनतम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2000 तक देश में खाद्त तेलों की कुल आवश्यकता 84.18 लाख मी. टन आंकी गई है।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमानित तिलहनों के 260 लाख मी.टन के लक्षित उत्पादन के आधार पर निकाला गया खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन वर्ष 2000 में 75.20 लाख मी.टन का है।

(ग) देश में खाद्य तेल उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :-

(i) अब तक उत्पादन में हुई वृद्धि मुख्य तौर पर इसके क्षेत्र में वृद्धि के कारण है । अब उत्पादकता, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में अभी कम है,मैं वृद्धि करने के उपायों पर बल दिया जाएगा;

(ii) तिहलन उत्पादन कार्यक्रम के क्रियान्वययन हेतु प्रयासों को तेज करना,क्रमिक फसलों,अन्तवर्ती फसलों के जरिए क्षेत्र विस्तार करना;

(iii) तेल ताड़ विकास हेतु सहायता;

(iv) मिनी किटों, स्प्रिंकलर सेटों, उन्नत कृषि उपकरणों और रसायनों आदि का वितरण । इसके अलावा उत्पादन प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए किसानों के खेतों में फ्रन्ट लाइन और सामान्य प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं;

(v) प्रसंस्करण यूनिटों के आधुनिकीकरण हेतु उपकरणों की पहचान ।

(घ) तिलहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में पर्याप्त मात्रा में आवाजाही को देखते हुए खाद्य तेलों के राज्यवार वार्षिक उत्पादन की उपयुक्त रूप में गणना करना संभव नहीं है ।

(ड.) अप्रैल, 97 के अंत में स्वदेशी खाद्य तेल और आयातित आर बी डी पामोलीन के तुलनात्मक थोक मूल्य निम्नवत हैं :-

	मूल्य रु. प्रति मी. टन
मुम्बई में मूंगफली का तेल	36,600/-
कलकत्ता में सरसों धानी	30,800/-
मुम्बई में रेपसीड तेल	28,800/-
मुम्बई में सोयाबीन तेल	29,100/-
आर बी डी पामोलीन	641.5 अमरीकी डालर
(लागत,बीमा,भाड़ा, सहित कांडला में)	(मई,97 मलेशिया से डिलीवरी)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी. एस.) के अंतर्गत जनसंख्या का प्रतिशत

4483. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे :** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या घनत्व बहुल प्रदेशों उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, और मध्य प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आती है;

(ख) क्या उक्त प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अनसंख्या दक्षिणी प्रदेशोम तमिलनाडु केरल इत्यादि से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जनसंख्या बहुल प्रदेशों में वितरण प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या कठिनाइयां हैं और इनके निराकरण के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ।

कृषि मंत्री खाद्य मंत्री और नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ग) वर्तामान नीति के

अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली सर्वसुलभ स्वरूप की है । इसलिए उत्तर प्रदेश,बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तथा केरल आदि सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की समूची आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आती हैं ।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों पर केन्द्रित करने हुए प्रवाही बनाया गया है । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वर्गीय प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की कार्य प्रणाली को अपनाकर योजना आयोग द्वारा लगाए गए अनुमानों के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान की जा रही है । गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विशेष राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर 10 कि. ग्रा. प्रति महीने की दर से खाद्यान्न जारी किए जाएंगे । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों के आवंटन का हिसाब गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रख कर पिछले 10 में खाद्यान्न के औसत उठान के आधार पर किया गया है । राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित दर दुकानों के लिए निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करने तथा जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट से लेकर आपूर्ति निरीक्षक के स्तर तक से उद्देश्य-पूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करने तथा राज्य स्तरों पर सर्तकता समितियां गठित की जानी हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्यपद्धति में अधिक पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है । इसका ब्यौरा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों में दिया गया है जिनको 24.2.97 को दोनों सदनों के पटलों पर रख दिया गया था । यह उम्मीद की जाती है कि इन उपायों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ज्यादा प्रभावी बनेगी ।

Study on Vehicular Pollution in the Country

4484. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any study has been undertaken by Government directly or through some agency or study group, regarding the polluting effects of automobiles in Indian cities and towns and the extent of it in other countries; and

(b) the details of the data available regarding the above and the steps taken by Government or being considered by Government to check growth of pollution due to the non-implementation of pollution control measures or the lack of sufficient initiatives from Government?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) and (b) The Central Pollution Control Board have conducted major surveys to assess the vehicular pollution in 12 major matropolitan cities of the country. The surveys show that:

*Pollution load in Delhi almost equals the combined pollution load of Mumbai, Calcutta and Madras.

*Load due to emissions of carbon monoxide (64%) and hydrocarbons (22%) is the highest in all the cities. This is followed by oxides of nitrogen(12%). Emissions of sulphur dioxide are negligible.

*The major contributors to carbon monoxide and hydrocarbons are the two-wheelers and three wheelers which are mostly powered by the two-stroke engines.

The major contributors of oxide nitrogen are the diesel driven trucks and buses.

According to the Report of UNEP-WHO on "Global Pollution and Health", 1988, Delhi is the fourth most polluted city in terms of suspended particulate matter and 27th in terms of sulphur dioxide. 1st, 2nd and 3rd polluted city in the world are: Kuwait, Shenyang (China) and Xian (China). Whereas Mumbai and Calcutta are at 13th and 6th positions respectively in terms of suspended particulate matter.

A number of measures are being taken/proposed for controlling vehicular pollution in the country. These include the following:

(i) Gross emission standards for on-road vehicles and mass emission standards for all categories of new vehicles have been notified under the